

ग्रामीण युवाओं के उद्यमशीलता विकास में प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवाओं की भूमिका

रणधीर सिंह¹, डॉ. सचिन कुमार²

¹शोधार्थी, ²प्रोफेसर

कृषि-विभाग

विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर म.प्र.

सारांश : ग्रा भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ युवा वर्ग देश की सबसे बड़ी जनसांख्यिकीय शक्ति है। ग्रामीण युवाओं में उद्यमशीलता का विकास न केवल रोजगार सृजन का माध्यम है, बल्कि स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा ग्रामीण विकास का आधार भी है। किन्तु कौशल, तकनीकी ज्ञान, वित्तीय साक्षरता, विपणन क्षमता तथा व्यवसाय प्रबंधन संबंधी जानकारी के अभाव में अधिकांश ग्रामीण युवा सफल उद्यमी नहीं बन पाते। इस शोध-पत्र का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के उद्यमशीलता विकास में प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवाओं की भूमिका का विश्लेषण करना है।

अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों एवं उपलब्ध साहित्य पर आधारित है। शोध में यह पाया गया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि विज्ञान केंद्र तथा MSME विकास संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं की उद्यमशील क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उचित प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवाएँ आत्मविश्वास, नवाचार, जोखिम वहन क्षमता तथा व्यवसाय की सफलता की संभावना को बढ़ाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की उद्यमिता भारत के समावेशी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बनती जा रही है। ग्रामीण युवाओं में नवाचार, रोजगार सृजन तथा स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं, किन्तु वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता उनके उद्यम स्थापना एवं विस्तार में प्रमुख बाधा के रूप में सामने आती है।

इस समीक्षा शोध-पत्र का उद्देश्य ग्रामीण युवा उद्यमिता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के मध्य संबंध का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन में विभिन्न सरकारी योजनाओं, बैंकिंग संस्थानों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्रों में वित्तीय पहुँच अधिक है, वहाँ ग्रामीण युवाओं की उद्यमिता अपेक्षाकृत अधिक सफल एवं टिकाऊ है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि वित्तीय साक्षरता, तकनीकी प्रशिक्षण तथा संस्थागत सहयोग ग्रामीण उद्यमिता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य संकेतक : ग्रामीण युवा, उद्यमशीलता, प्रशिक्षण, परामर्श सेवाएँ, कौशल विकास, आत्मनिर्भर भारत।



I. परिचय

भारत में ग्रामीण विकास का आधार कृषि के साथ-साथ ग्रामीण उद्यमशीलता भी है। बढ़ती बेरोजगारी, सीमित कृषि आय तथा रोजगार के अवसरों की कमी के कारण ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। यदि ग्रामीण युवाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान, व्यवसायिक परामर्श तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए तो वे स्थानीय संसाधनों पर आधारित सफल उद्यम स्थापित कर सकते हैं।

सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास योजनाएँ ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु प्रेरित कर रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं में तकनीकी दक्षता, व्यवसाय योजना निर्माण, विपणन रणनीति तथा डिजिटल प्रबंधन की क्षमता विकसित करते हैं, जबकि परामर्श सेवाएँ व्यवसाय स्थापना से लेकर विस्तार तक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

II. अनुसंधान पद्धति

विवरण	जानकारी
अनुसंधान प्रकार	वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक
डेटा स्रोत	द्वितीयक आँकड़े
स्रोत	शोध-पत्र, सरकारी रिपोर्ट, NITI Aayog, MSME, NABARD, NSDC
विश्लेषण विधि	गुणात्मक एवं वर्णनात्मक विश्लेषण

III. ग्रामीण युवाओं में उद्यमशीलता का महत्व

ग्रामीण उद्यमशीलता स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके रोजगार सृजित करती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि, गरीबी उन्मूलन तथा पलायन में कमी आती है। कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, डिजिटल सेवाएँ तथा ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध हैं।

IV. प्रशिक्षण सेवाओं की भूमिका

प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को निम्नलिखित कौशल प्रदान करते हैं:-

1. व्यवसाय योजना तैयार करना
2. वित्तीय प्रबंधन
3. डिजिटल मार्केटिंग
4. उत्पादन तकनीक
5. गुणवत्ता नियंत्रण
6. ग्राहक प्रबंधन
7. ऑनलाइन व्यापार
8. नेतृत्व क्षमता
9. संचार कौशल



इन प्रशिक्षणों से युवा रोजगार खोजने के बजाय रोजगार देने वाले बनते हैं।

तालिका 1: प्रशिक्षण से विकसित होने वाले प्रमुख कौशल

प्रशिक्षण क्षेत्र	विकसित कौशल	संभावित लाभ
तकनीकी प्रशिक्षण	उत्पादन क्षमता	उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि
वित्तीय प्रशिक्षण	बजट एवं लेखांकन	लाभ में वृद्धि
विपणन प्रशिक्षण	ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मार्केटिंग	बिक्री में वृद्धि
डिजिटल प्रशिक्षण	सोशल मीडिया एवं ई-कॉमर्स	नए बाजार तक पहुँच
नेतृत्व प्रशिक्षण	निर्णय क्षमता	सफल व्यवसाय संचालन

V. परामर्श सेवाओं की भूमिका

प्रशिक्षण के बाद परामर्श सेवाएँ उद्यम स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। विशेषज्ञ परामर्शदाता व्यवसाय चयन, बाजार विश्लेषण, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, ऋण प्राप्त करने तथा व्यवसाय विस्तार में सहायता प्रदान करते हैं।

परामर्श सेवाओं के प्रमुख क्षेत्र: -

1. व्यवसाय चयन
2. बाजार सर्वेक्षण
3. बैंक ऋण मार्गदर्शन
4. सरकारी योजनाओं की जानकारी
5. कानूनी पंजीकरण
6. जीएसटी एवं कर प्रणाली
7. डिजिटल भुगतान
8. ब्रांडिंग एवं विपणन

तालिका 2: परामर्श सेवाओं का प्रभाव

परामर्श सेवा	लाभ
व्यवसाय योजना	जोखिम में कमी
वित्तीय सलाह	पूंजी प्रबंधन
विपणन मार्गदर्शन	ग्राहकों की संख्या बढ़ना
कानूनी सहायता	व्यवसाय का सुचारु संचालन
डिजिटल सलाह	ऑनलाइन बिक्री में वृद्धि



VI. सरकारी योजनाओं का योगदान

भारत सरकार ने अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की हैं जो ग्रामीण युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देती हैं।

तालिका 3: प्रमुख सरकारी योजनाएँ

योजना	उद्देश्य	लाभार्थी
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	कौशल प्रशिक्षण	ग्रामीण युवा
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य	रोजगारपरक प्रशिक्षण	ग्रामीण बेरोजगार
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वरोजगार	स्वयं सहायता समूह
मुद्रा योजना	ऋण सुविधा	सूक्ष्म उद्यमी
स्टार्टअप इंडिया	नवाचार आधारित उद्यम	युवा उद्यमी

VII. प्रशिक्षण एवं उद्यमशीलता के बीच संबंध

प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं में आत्मविश्वास, नवाचार, तकनीकी दक्षता एवं व्यवसाय संचालन क्षमता अधिक विकसित होती है।

तालिका 4: प्रशिक्षण का प्रभाव

संकेतक	प्रशिक्षण पूर्व	प्रशिक्षण पश्चात
तकनीकी ज्ञान	निम्न	उच्च
आत्मविश्वास	कम	अधिक
व्यवसाय योजना	सीमित	प्रभावी
डिजिटल कौशल	कम	अच्छा
विपणन क्षमता	सीमित	बेहतर

VIII. ग्रामीण युवाओं के समक्ष चुनौतियाँ

भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है और इसकी लगभग दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण युवा देश के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। यदि इस युवा शक्ति को उचित शिक्षा, कौशल, रोजगार तथा उद्यमशीलता के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान कर सकती है। किंतु वास्तविकता यह है कि ग्रामीण युवाओं को अनेक ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके व्यक्तिगत विकास, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता की संभावनाओं को सीमित कर देती हैं।

इन चुनौतियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, कौशल विकास के सीमित अवसर, वित्तीय संसाधनों की कमी, आधुनिक तकनीक तक सीमित पहुँच, विपणन संबंधी कठिनाइयाँ, सामाजिक रूढ़िवादिता, सरकारी योजनाओं की अपर्याप्त जानकारी तथा आधारभूत सुविधाओं का अभाव प्रमुख हैं। इन समस्याओं के कारण ग्रामीण युवाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता और वे बेरोजगारी, पलायन तथा आर्थिक असुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं।



ग्रामीण युवाओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी शिक्षा की गुणवत्ता, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण, आधुनिक पाठ्यक्रम तथा रोजगारोन्मुखी शिक्षा का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अधिकांश ग्रामीण शिक्षण संस्थानों में प्रयोगशालाएँ, डिजिटल संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक तथा करियर मार्गदर्शन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। परिणामस्वरूप युवा केवल औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उनमें व्यावसायिक दक्षता और उद्यमशीलता से संबंधित आवश्यक कौशल विकसित नहीं हो पाते। बदलते आर्थिक परिवेश में उद्योगों और सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित न होने के कारण वे रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं।

रोजगार के सीमित अवसर भी ग्रामीण युवाओं के लिए गंभीर चुनौती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जबकि कृषि जोतों का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है और कृषि आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण युवाओं को वर्ष भर नियमित रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। स्थानीय स्तर पर उद्योगों, लघु एवं कुटीर उद्यमों तथा सेवा क्षेत्र के सीमित विकास के कारण शिक्षित युवा भी बेरोजगार रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने के लिए विवश हो जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन की कमी उत्पन्न होती है और स्थानीय विकास की गति प्रभावित होती है।

उद्यमशीलता के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले ग्रामीण युवाओं के समक्ष वित्तीय संसाधनों की कमी सबसे बड़ी बाधा है। अधिकांश युवाओं के पास स्वयं की पूंजी नहीं होती तथा बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़, संपार्श्विक, व्यवसाय योजना तथा वित्तीय ज्ञान का अभाव होता है। यद्यपि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया तथा अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी अनेक ग्रामीण युवाओं को बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता, जानकारी की कमी तथा समय पर ऋण स्वीकृति न मिलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुँच के कारण अनेक संभावित उद्यम प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं।

तकनीकी एवं डिजिटल संसाधनों की कमी भी ग्रामीण युवाओं की प्रगति में बाधक है। वर्तमान समय में व्यवसाय, शिक्षा, विपणन तथा रोजगार के अधिकांश अवसर डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की धीमी गति, डिजिटल उपकरणों की अनुपलब्धता तथा डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण युवा इन अवसरों का समुचित लाभ नहीं उठा पाते। ऑनलाइन विपणन, ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान प्रणाली, सोशल मीडिया ब्रांडिंग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेवाओं का उपयोग सीमित रहने से उनके व्यवसाय की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी प्रभावित होती है। डिजिटल विभाजन ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच अवसरों की असमानता को और अधिक बढ़ाता है।

बाजार तक पहुँच एवं विपणन संबंधी समस्याएँ भी ग्रामीण उद्यमियों के लिए बड़ी चुनौती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों की गुणवत्ता होने के बावजूद उचित पैकेजिंग, ब्रांडिंग, परिवहन, भंडारण तथा विपणन नेटवर्क के अभाव में उन्हें उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। अधिकांश युवा स्थानीय बाजारों तक ही सीमित रह जाते हैं और राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच नहीं बना पाते। मध्यस्थों पर निर्भरता के कारण लाभ का बड़ा हिस्सा बिचौलियों के पास चला जाता है, जिससे उद्यम की लाभप्रदता कम हो जाती है। आधुनिक विपणन तकनीकों एवं डिजिटल मार्केटिंग का सीमित ज्ञान भी इस समस्या को और अधिक गंभीर बना देता है।



सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी ग्रामीण युवाओं के उद्यमशील विकास को प्रभावित करते हैं। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पारंपरिक सोच, जोखिम से बचने की प्रवृत्ति तथा सरकारी नौकरी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मानसिकता प्रचलित है। उद्यम शुरू करने को जोखिमपूर्ण माना जाता है, जिसके कारण परिवार और समाज का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। विशेष रूप से ग्रामीण युवतियों को सामाजिक प्रतिबंधों, सीमित गतिशीलता, लैंगिक भेदभाव तथा संसाधनों तक कम पहुँच जैसी अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में उनकी उद्यमशील क्षमता का पूर्ण विकास नहीं हो पाता।

सरकारी योजनाओं एवं संस्थागत सहायता की जानकारी का अभाव भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा स्वरोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, कृषि-आधारित उद्योग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, किंतु ग्रामीण युवाओं तक इन योजनाओं की जानकारी प्रभावी ढंग से नहीं पहुँच पाती। सूचना के अभाव, जटिल आवेदन प्रक्रिया तथा उचित मार्गदर्शन की कमी के कारण अनेक पात्र युवा इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। यदि प्रशिक्षण संस्थान, पंचायतें, स्वयं सहायता समूह तथा स्थानीय प्रशासन मिलकर जागरूकता अभियान चलाएँ तो इन योजनाओं की पहुँच अधिक प्रभावी हो सकती है।

आधारभूत संरचना की कमी भी ग्रामीण उद्यमशीलता के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। अनेक गाँवों में गुणवत्तापूर्ण सड़क, परिवहन, विद्युत आपूर्ति, इंटरनेट, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज तथा औद्योगिक अवसंरचना का अभाव देखा जाता है। इन सुविधाओं की कमी के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है और बाजार तक पहुँच कठिन हो जाती है। साथ ही स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सेवाओं की सीमित उपलब्धता भी युवाओं की उत्पादकता और जीवन-स्तर को प्रभावित करती है। बेहतर आधारभूत संरचना के बिना ग्रामीण उद्योगों का सतत विकास संभव नहीं है।

परामर्श एवं मेंटरशिप की कमी भी एक गंभीर समस्या है। अनेक युवा व्यवसाय प्रारंभ तो कर लेते हैं, किंतु व्यवसाय प्रबंधन, लेखांकन, कराधान, विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण तथा कानूनी प्रक्रियाओं के संबंध में उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण उनका उद्यम लंबे समय तक सफल नहीं रह पाता। यदि प्रशिक्षण के साथ अनुभवी उद्यमियों, उद्योग विशेषज्ञों तथा वित्तीय सलाहकारों की नियमित मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाए तो व्यवसाय की सफलता की संभावना उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकती है। इस प्रकार प्रशिक्षण और परामर्श सेवाओं का समन्वित मॉडल ग्रामीण युवाओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण युवाओं के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ बहुआयामी हैं और इनका समाधान भी समग्र दृष्टिकोण से किया जाना आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण, विपणन सहायता, आधारभूत संरचना का विकास, प्रभावी परामर्श सेवाएँ तथा सरकारी योजनाओं की सरल एवं पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करके ही ग्रामीण युवाओं को सफल उद्यमी बनाया जा सकता है। यदि सरकार, शैक्षणिक संस्थान, वित्तीय संस्थाएँ, गैर-सरकारी संगठन तथा निजी क्षेत्र मिलकर समन्वित प्रयास करें, तो ग्रामीण युवा न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार सृजन करने तथा समावेशी एवं सतत विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

समस्या	प्रभाव
वित्तीय संसाधनों की कमी	व्यवसाय प्रारम्भ करने में कठिनाई
तकनीकी ज्ञान का अभाव	कम उत्पादकता



बाजार जानकारी का अभाव	बिक्री प्रभावित
डिजिटल साक्षरता की कमी	ऑनलाइन अवसर सीमित
परामर्श सेवाओं की कमी	व्यवसाय विफलता की संभावना

IX. चर्चा

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केवल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण के साथ निरंतर परामर्श एवं मार्गदर्शन भी आवश्यक है। जिन युवाओं को प्रशिक्षण के बाद व्यवसायिक सलाह, बैंकिंग सहायता, विपणन सहयोग तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उनके उद्यम अधिक सफल रहे। प्रशिक्षण और परामर्श के समन्वित मॉडल से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, आय वृद्धि तथा स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है।

X. निष्कर्ष

ग्रामीण युवाओं के उद्यमशीलता विकास में प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रशिक्षण युवाओं को तकनीकी एवं प्रबंधकीय दक्षता प्रदान करता है, जबकि परामर्श सेवाएँ व्यवसाय की स्थापना, संचालन और विस्तार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराती हैं। सरकारी योजनाओं, वित्तीय संस्थानों और प्रशिक्षण एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। यदि प्रशिक्षण, परामर्श, वित्तीय सहायता और विपणन समर्थन को एकीकृत रूप में उपलब्ध कराया जाए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है।

संदर्भ

1. अख्तर, एफ. (2023). भारत में ग्रामीण युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने में स्किल इंडिया कार्यक्रमों की भूमिका। फॉर्मोसा जर्नल ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2(10), 2891–2902.
2. किरण, पठानिया, ए., विकास, और मीना, एस. एस. (2025). करियर के तौर पर उद्यमिता चुनने में ग्रामीण युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ: हरियाणा का एक केस स्टडी। इंडियन जर्नल ऑफ़ एक्सटेंशन एजुकेशन, 61(1), 99–103.
3. कुमार, ए., और सिंह, आर. (2014). ग्रामीण युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक सफल मॉडल के घटक। इंडियन जर्नल ऑफ़ एक्सटेंशन एजुकेशन, 50(3–4), 113–118.
4. कुमार, पी., और कुमरा, आर. (2021). भारत में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान: एक व्यवस्थित समीक्षा। प्रबंधन: इंडियन जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट, 14(10), 39–51.
5. डाना, एल. पी. (2000). भारत में उद्यमी तैयार करना। जर्नल ऑफ़ स्मॉल बिज़नेस मैनेजमेंट, 38(1), 86–91.
6. डाना, एल. पी. (2001). एशिया में उद्यमियों की शिक्षा और प्रशिक्षण। एजुकेशन + ट्रेनिंग, 43(8–9), 405–416.
7. डैश, डी., अमरदीप, ए., कामेश्वरी, वी. एल. वी., और भारद्वाज, एन. (2021). भारत के ओडिशा राज्य में आदिवासी युवाओं की कृषि-उद्यमिता प्रशिक्षण संबंधी ज़रूरतें। द इंडियन जर्नल ऑफ़ एग्रीकल्चरल साइंसेज, 91(11), 1580–1585.
8. सिंह, आर. आर., और कुमार, सी. (2024). ग्रामीण उद्यमिता क्षमता विकास के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, 1(2), 84–93.



9. सिंह, एस., सोनू के., दोहरे, आर. के., सिंह, एस., और साहू, एस. (2026). कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के उद्यमी व्यवहार को समझना। इंडियन जर्नल ऑफ़ एक्सटेंशन एजुकेशन, 62(2), 10–14.
10. सिंह, डी. वी., और सिंह, एस. के. (2022). कृषि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कृषि उद्यमिता और ग्रामीण उद्यमों का विकास। इंडियन जर्नल ऑफ़ एक्सटेंशन एजुकेशन, 58(4), 38–42.

